



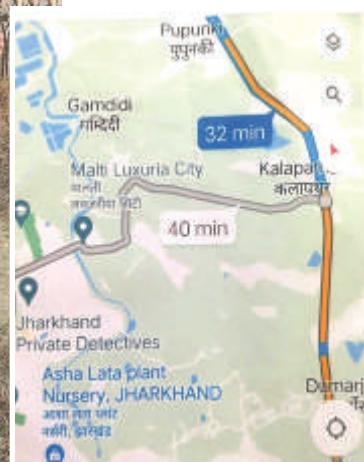
बोकारो :: रविवार, 26 मार्च, 2023

20 गांवों को मिलेगा 'विकास-कनेक्शन', ग्रामीणों में हृषि

कार्यालय संचाददाता

बोकारो : गांधीवादी नेता एवं इस क्षेत्र के प्रथम विधायक हरदयाल शर्मा के गांव चिकिसिया सहित आसपास के 20 गांवों में बड़ी खुशी मिली है। 57 वर्षों के बाद उनके गांवों का विकास से जुड़ाव हो सकेगा और तरकी की किरणें पहुंच सकेंगी। धनबाद के सांसद पशुपति नाथ सिंह ने डीएमएफटी निधि से इस पथ के निर्माण की अनुशंसा कर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बड़ी सौगत दी है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय उच्च पथ (एनएच-32) के चास मुफर्रिसल थाना के दक्षिण से एक सड़क गोमदीडीह नाला तक पूर्व से निर्मित है। जबकि, कालापाथर पंचायत अन्तर्गत गोमदीडीह (नाला) गांव की पुलिया से गांव होते हुए नावाडीह पंचायत के मूर्तिटांड़ होते हुए बोकारो इस्पात नगर के सेक्टर-6 स्थित गरगा पुल तक महज दो किलोमीटर सड़क का निर्माण आज तक नहीं हो सका है।

कालापाथर (चिकिसिया) पंचायत एवं नावाडीह पंचायत के 20-25 गांव के लोगों को बोकारो स्टील



सियासत

बिहार प्रदेश भाजपा को मिला नया 'सप्लाट', सांगठनिक ढांचे में बड़ा बदलाव किया गया

जातिगत राजनीति में अब 'कुशवाहा' दौर



विशेष संचाददाता

पटना : भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुनै को पूरी तरह ध्वस्त करना चाहती है। भाजपा की सोची-समझी रणनीति का ही नीतीजा है कि कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे करीबी रहे उपेन्द्र कुशवाहा व आरसीपी सिंह सहित कई दिग्गज नेता उनके खिलाफ मुख्य हैं। अब भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अपने सांगठनिक ढांचे में बड़ा बदलाव किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा ने संजय जायसवाल को

हटाकर सप्लाट चौधरी को उनकी जगह प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की कमान सौंपी है। सप्लाट चौधरी फिलहाल बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं और कोई समाज से आते हैं। श्री चौधरी पिछली एनडीए सरकार में मंत्री थे। भाजपा में आने के बाद पार्टी ने उन्हें विधायक, विधान पार्षद, मंत्री, नेता प्रतिपक्ष और अब प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। दरअसल, बिहार की राजनीति में 'जाति' का बड़ा ही महत्व रहा है। बिहार की जातिगत राजनीति में अब मुस्लिम, यादव और कुर्मी के बाद 'कुशवाहा' दौर चल पड़ा है। क्योंकि, बिहार की राजनीति इन दिनों कुशवाहा वोट के इर्द गिर्द धूम रही है। पहले जदयू ने प्रदेश अध्यक्ष सहित कुल 24 लोगों को जंबो कमिटी में शामिल कर अपना पता खोल दिया था। अब चूंकि लोहा को लोहा ही काटता है, इसलिए भाजपा ने भी अपना प्रदेश अध्यक्ष सप्लाट चौधरी को बनाकर अपनी रणनीति का खुलासा कर दिया है। दरअसल, नीतीश कुमार के विरुद्ध चुनावी युद्ध को संतुलित करने में सबसे कारगर वोट कुशवाहा का ही माना जा रहा है।

35 सीटों पर जीत का लक्ष्य

दरअसल, भाजपा की नजर बिहार की 40 में 35 लोकसभा सीटों पर है, जहां वह अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है। क्योंकि, इससे पहले ही दिल्ली में पाटी के उच्च पदस्थ नेताओं के साथ हुई बैठक में आगामी आम चुनाव में बिहार की 40 में से 35 लोकसभा सीटों पर जीत का लक्ष्य तय किया गया था। इसके लिए संगठन को मजबूत करने और सांगठनिक स्तर पर बड़े बदलाव करने पर सहमति बनी थी। इसी में तय किया गया था कि प्रदेश अध्यक्ष भी नया बनेगा। तब भाजपा की ओर से इसकी घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन अब सप्लाट चौधरी पर मुहर लगा दी गई।

सांसद पीएन सिंह ने दिखाई गंभीरता

सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएमएफटी फंड से दो किलोमीटर इस लिक रोड को प्राथमिकता देते हुए बनाने की अनुशंसा की है। मालूम हो कि इस पथ की लम्बाई लगभग चार किलोमीटर है, जिसमें चास मुफर्रिसल थाना से लेकर दो किलोमीटर सड़क 5-6 साल पहले ही बना दी गई है, परन्तु आगे सड़क नहीं होने के कारण लोग इस रास्ते का समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।



उल्लेखनीय है कि देश की आजादी के बाद स्वर्गीय हरदयाल शर्मा इस क्षेत्र के पहले विधायक थे, जिनके प्रयास से ही पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मानभूम जिले में स्थित चास और चंदनकियारी सहित धनबाद को काटक बिहार में जोड़ा जा सका और देश के सबसे बड़े स्वदेशी इस्पात कारखाने की स्थापना बोकारो में संभव हो सकी।

लेकिन मात्र दो किलोमीटर सड़क नहीं होने से किसान-मजदूर, छाटे व्यापारी अथवा बीमार मरीजों को नदी के इस पार आने-जाने में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के पहले वाले विद्यार्थी होंगे या शादी- विवाह अथवा अन्य आयोजनों में बोकारो आने-जाने वाले लोग हों, सबों को काफी खर्च का बोझ भी उठाना पड़ता है।

इसके अलावा, चास नगर निगम तथा केन्द्र व राज्य की संयुक्त योजना के तहत सिटी बस परिचालन की सेवा शुरू होनी है, उससे भी इस क्षेत्र के लोग वर्चित समझते रहे हैं। लेकिन, सांसद श्री सिंह की ओर से उपायकृत को अनुशंसा-पत्र लिखे जाने से उम्मीद जगा है कि इन गांवों के लोगों को जल्द ही बड़ी राहत मिलेगी।

भाजपा ने थामा पिछड़ों का दामन

सप्लाट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाये जाने के साथ यह बात साफ हो गई है कि भाजपा ने पिछड़ों की राजनीति का दामन थाम लिया है। जानकारों की माने तो बिहार में पिछड़ी जाति में यादव के बाद कुशवाहा समाज का सबसे जायदा वोट है। लगभग 7 से 9 प्रतिशत वोटों का आधार रखने वाला कुशवाहा समाज अब 'लव' की छतरी तले राजनीति को अंजाम देना चाहता है। क्योंकि, इसके पहले कम वोट बैंक के बाद भी यह समाज अब तक कुर्मी जाति से आने वाले नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजनीति करने के लिए बाध्य था। लेकिन, अब उसे अपने अलग नेतृत्व की भूमिका मिल गई है।

जदयू ने छिनवाई विधान परिषद की सदस्यता

बिहार में आज जब नीतीश कुमार एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल के साथ महागठबंधन-2 की सरकार चला रहे हैं तो विधान परिषद के अन्दर और बाहर सप्लाट चौधरी विधायक की सबसे बुलंद आवाज माने जाते हैं। लेकिन, सप्लाट चौधरी जब जदयू के साथ थे तो नीतीश कुमार ने न सिर्फ सप्लाट चौधरी से किनारा कर लिया, बल्कि दल-बदल कानून के आधार पर उनकी विधान परिषद की सदस्यता भी छिनवा दी थी। लेकिन, समय बदल और परिस्थितियां बदलीं, नीतीश कुमार फिर भाजपा के साथ आ गए। लेकिन, तब तक सप्लाट चौधरी ने भाजपा के अंदर अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी। 16 नवंबर 1968 को जन्मे सप्लाट चौधरी उर्फ राकेश कुमार फिलहाल भाजपा की ओर से बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। इनके पिता शकुनी चौधरी सांसद और मंत्री रह चुके हैं।



- संपादकीय -

राजनीतिक टकराव बढ़ने के आसार

सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी के खिलाफ फैसला आने और उसके अगले ही दिन लोकसभा सचिवालय द्वारा राहुल की संसद सदस्यता खत्म किये जाने की घोषणा के बाद देश में राजनीतिक टकराव के आसार बढ़ने लगे हैं। इस मामले ने सभी विपक्षी राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि, इस मामले में जो कुछ भी हुआ, वह नियम-कानून के अनुरूप ही है। लेकिन, इसने राहुल गांधी को संजीवनी जरूर दे दी है। यही वजह है कि कांग्रेस ने इसे अगले लोकसभा चुनाव में भुनाने की कोशिश तेज कर दी है। मजे की बात यह है कि जिस कानून के तहत राहुल गांधी की संसद सदस्यता छिनी है, वर्ष 2013 में वह खुद उन्हीं के हस्तक्षेप से बना था। उस समय की यूपीए सरकार द्वारा इस कानून से राहत दिलाने संबंधी लाये जा रहे अध्यादेश की कॉपी राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से फाड़ दी थी। लिहाजा, विरोधी ताल ठोककर यह तर्क दे सकते हैं कि जिस कानून की हिमायत खुद राहुल ने की थी, आज जब उसी कानून की गिरफ्त में वह खुद आ चुके हैं तो फिर वह इतनी हाय-तौब्बा क्यों मचा रहे हैं? लेकिन, अहम सवाल है कि राहुल गांधी के मुद्दे पर एकजुट हो चुका विपक्ष जनता के बीच इसे किस कदर परोसता है और आम लोग इसे किस नजरिये से देखते हैं। हालांकि, अदालत ने सजा पर अमल करने से पहले खुद राहुल गांधी को इसके खिलाफ अपील के लिए 30 दिनों की मोहलत दी है और राहुल गांधी को संसद से अयोग्य करार दिये जाने का यह मामला देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच भी चुका है। राहुल गांधी खुद भी यह कबूल चुके हैं कि अब विपक्ष को एकजुट करने का एक हथियार मिल गया है। सूरत की अदालत द्वारा मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा और उनकी संसद सदस्यता खत्म किये जाने के विरोध में कांग्रेस ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है और निशाने पर हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। क्योंकि, लोकसभा सचिवालय ने न्यायालय के फैसले के बाद जिस तरह की जल्दबाजी दिखाई, उस पर सवाल खड़े होना लाजिमी है। कांग्रेस भी इसी बात पर ज्यादा जोर दे रही है। विपक्ष को यह एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। यही कारण है कि राजनीति में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दुश्मन गर्जना करने लगे हैं। अब सभी विपक्षी दलों को एकजुट कर 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को शिक्षण देने की कवायद तेज हो गई है। हालांकि, पूरा विपक्ष कांग्रेस ने तृत्व के साथ आने पर सहमत होगा या नहीं, फिलहाल कहना मुश्किल है। क्योंकि, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा नेता अखिलेश यादव ने कांग्रेस को छोटे दलों को आगे कर साथ आने की नसीहत दी है। विपक्ष एक बार फिर इमरजेंसी की याद दिला रहा है। इनका कहना है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन, देश की जनता पर इसका कितना असर होगा, यह तो आने वाले समय में साफ हो सकेगा।

आप अपने विचार अथवा अपनी रचनाएं हमें निम्नलिखित ई-मेल पर भेज सकते हैं—
mithilavarnan@gmail.com, Contact : 9431379234

Join us on /mithilavarnan

Visit us on : www.varnanlive.com

(किसी भी कानूनी विवाद का निवारा केवल बोकारो कोर्ट में ही होगा।)

खालिस्तानी खलनायकों का खुला खेल- एक चुनौती



बिसवेन (ऑस्ट्रेलिया) से
मोद प्रकाश



फोटो सामार -
ऑस्ट्रेलिया टुडे

पिछले कुछ महीनों से खालिस्तानी उपद्रवियों द्वारा भारत समेत विश्व के कई शहरों में भारतीय सरकारी दफतरों पर हमले किये जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिसबेन स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास, इंग्लैंड में लंदन स्थित भारतीय दूतावास, लॉस एंजेलेस में उठर हरी है और अगर उठर ही है तो क्या यह सिख समुदाय की मांग है? वही सिख समुदाय, जो सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए वीरांगना माताओं द्वारा अपने पुत्रों के बलिदान से बना। माताओं ने अपने पुत्रों को गुरुओं के चरणों में समर्पित कर दिया यह कहकर कि राष्ट्र और धर्म की राह में अगर शहादत होगी तो उनके धरती का कर्ज उत्तर जाएगा। क्या, वही सिख आज सनातन धर्म का शत्रु हो सकता है? क्या हम गुमराह लोगों को समुदाय से जोड़ रहे हैं?

इधर, भारत में 'वारिस पंजाब दे' के पूरे संगठन पर देशद्रोह और सामाजिक उपद्रव के मामले को लेकर सैकड़ों गिरफ्तारियां की गई और संगठन के सरगरना अमृतपाल सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया। इन असामाजिक और देशविरोधी ताकतों से सख्ती और सफलता से निपटने में पंजाब पुलिस और भारतीय सासन तंत्र पूरी तरह से सक्षम है और मेरा यह पूरा विश्वास हमेशा रहा है कि सही समय पर उचित कार्यवाही हो ही जाएगी। यह लेख लिखे जाने तक अमृतपाल भगोड़ा है और पुलिस उसे हर जगह खोज रही है। आज नहीं तो कल पुलिस उसे किसी भी हालत में खोज ही लैगी। यहां इस पोस्ट में मैं इस समस्या के अन्य पहलुओं पर बात करना चाहता हूँ।

गत सप्ताह दिल्ली में एक बड़े सिख समुदाय के जयंते ने ब्रिटेन दूतावास के सामने लंदन में भारतीय दूतावास पर हमले के विरोध में प्रदर्शन किया। सवाल यह है कि

जान अपना दे दिया,
निडर अपने सिंह ने।
'राजगुरु', 'सुखदेव',
और 'भगत सिंह' ने॥

इन शहीदों पर है गर्व,
संग आँखें भी हैं नम।
श्रद्धा-सुमन इनको समर्पित,
है इन्हें शत्-शत् नमन॥

हिन्दी
कविता

देश के प्रति सब समर्पित,
देश-हित में कर्म हो।
देश-भक्ति जिसके लिए,
सबसे बड़ा धर्म हो॥



- सुधीर कुमार झा -
कोलकाता



एक बार फिर डराने लगी महामारी निपटने की हो रही पुरखा तैयारी

10-11 को देशभर में होगी मॉकड्रिल

ब्यरो संचाददाता

नई दिल्ली : दो साल के कोरोनाकाल के बाद देश अब पटरी पर लौटता आ रहा है, परंतु ऐसे में कोरोना (कोविड-19) महामारी के बढ़ते मामले एक बार फिर डराने लगे हैं। इसके साथ ही मौसमी इन्स्ट्रुएंजा के केस बढ़ने लगे हैं। हालांकि, पूरा देश इस आफत से निपटने के लिए एक बार फिर तैयारी में जुट गया है। इस बीच सरकार अस्पतालों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 10 और 11 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल की योजना बना रही है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि सभी जिलों के सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की स्वास्थ्य इकाइयां इस मॉकड्रिल में भाग लेंगी।

जारी की गई एडवाइजरी में वह भी कहा गया है कि फरवरी के मध्य से देश में कोविड-19 मामलों में क्रमिक लेनेकिन निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। इस समय, देश में अधिकांश कोरोना मामले केरल (26.4 प्रतिशत), महाराष्ट्र (21.7 प्रतिशत), गुजरात (13.9 प्रतिशत), कर्नाटक (8.6 प्रतिशत) और तमिलनाडु (6.3 प्रतिशत) में बढ़ाया जा रहा है। इसके बाद देश में कोरोना के मामले जैसी बीमारी (ईली) और गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी (सारी) के मामले पर कड़ी नजर रखने की सलाह दी गई है। पत्र में लिखा गया है कि कोरोना और बीमारी के त्वरित और प्रभावी प्रबंधन के लिए जरूरी उपायों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है। पत्र में लिखा गया है कि फरवरी के मध्य में कोरोना मामले तेजी से बढ़े हैं। खासकर केरल (26.4 प्रतिशत), महाराष्ट्र

मॉकड्रिल में सभी जिलों की

स्वास्थ्य इकाइयों को शामिल होने का निर्देश इसके अलावा कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉकड्रिल में सभी राज्यों को शामिल होने के लिए भी कहा गया है। अप्रैल की 10 और 11 तारीख को होने वाली मॉकड्रिल में आईसीयू बैठ, मेडिकल इविमर्मेंट्स, ऑक्सीजन और मैनपावर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। बढ़ते मामलों को देखते हुए आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय ने लिखी सभी राज्यों को चिट्ठी देश में इफ्लूएंजा (फ्लू) के साथ कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसको लेकर शनिवार को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के महानिर्देशक राजीव बहल और स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने संयुक्त रूप से राज्यों को कोरोना की रिथ्टि पर खास एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए। राज्यों को लिखी गई चिट्ठी में सरकार ने कोरोना की जांच बढ़ाने और बीमारी के त्वरित और प्रभावी प्रबंधन के लिए जरूरी उपायों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है। पत्र में लिखा गया है कि कोरोना और इन्स्ट्रुएंजा में कई समानताएं हैं। हालांकि सरल सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों का पालन करके इन दोनों बीमारियों को आसानी से रोका जा सकता है।

कोटोना केस में आया उछाल



146 दिन में सर्वाधिक 1590 नए मामले

गैरतब है कि देश में शनिवार को कोरोना के 1,590 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यह आंकड़ा बाते 146 दिन में सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही खबर लिखे जाने तक कोरोना के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 8,601 हो गयी है। वहीं, देश में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,47,02,257 हो गयी है। साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,30,824 हो गई है। शनिवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, कोरोना संक्रमण की दैनिक दर 1.33 प्रतिशत दर्ज की गई है वहीं साप्ताहिक संक्रमण दर 1.23 प्रतिशत हो गई है।

कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन की अपील
कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा शनिवार को जारी एक संयुक्त एडवाइजरी में कहा गया है कि पिछले कई हफ्तों में कुछ राज्यों में कोविड-19 की टेस्टिंग में गिरावट आई है। साथ ही वह भी पाया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नियरित मानकों की तुलना में वर्तमान में परीक्षण स्तर अपर्याप्त है। इसके देखते हुए सभी राज्यों को कोरोना जांच में बढ़ावा देने और लक्षणों की जानकारी देने के लिए भी कहा है।

CASHLESS FACILITY CASHLESS FACILITY CASHLESS FACILITY

शिवम् हॉस्पीटल में

सेल के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए

मोतियाबिन्द का ऑपरेशन
एवं लेंस लगाया जाता है।

E-2, LAXMI MARKET, SECTOR-4, B.S.CITY-827004
PH: 06542-232623/233475, MOB: 7488090631

